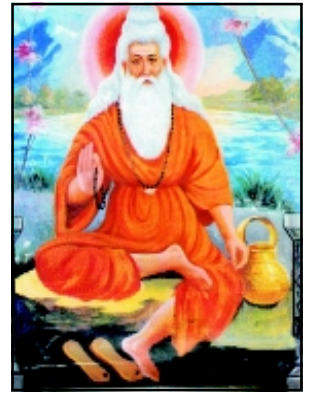




प्रकाशक/स्वामीत्व
रजनी (पुत्री-महेश धावनिया)

डाक पंजियन संख्या : JaipurCity/417/2020-22

श्री बाबा



प्रधान कार्यालय-सी-57, महेश नगर, जयपुर-15, मो.-9928260244

हिन्दी मासिक समाचार पत्र



7073909291

E-mail:shreebaba_2008@yahoo.com

वर्ष : 12

अंक : 12

आर.एन.आई. नं. : RAJHIN/2008/24962



जयपुर, 5 फरवरी, 2020

मूल्य : 5 रुपए प्रति

पृष्ठ : 4

अमीरी-गरीबी का भेद मिटाती है खादी: अशोक गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि खादी अमीरी-गरीबी और कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि स्वाभिमान और सम्मान



जाति-धर्म का भेद मिटाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा और सादगी के सिद्धांतों को खादी मूर्त रूप प्रदान करती है। हम सभी को खादी को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए और युवा पीढ़ी को भी इससे जोड़ना चाहिए। श्री गहलोत हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान में खादी के वैश्वीकरण पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित

का कारण है। खादी को लेकर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से खादी के प्रति नई पीढ़ी में रूचि जागृत होगी और खादी को एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में जो भी सुझाव आएंगे राज्य सरकार उन पर अमल करने का पूरा प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम होने के साथ ही महिला सशक्तीकरण का भी प्रमुख जरिया

है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खादी एवं खादी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए खादी वस्त्रों पर राजस्थान में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। श्री गहलोत ने कहा कि खादी के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं में नई पीढ़ी का रुझान कम देखने को मिलता है।

आज गांवों में रोजगार कम हो रहे हैं और बुनकर एवं कानिनों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे रोजगार भी बढ़े और बुनकरों-कानिनों की तादाद बढ़ सके। हमारा प्रयास होना चाहिए कि नई पीढ़ी को खादी से जोड़ा जाए उन्होंने कहा कि गांधी जी की 150वीं जयन्ती वर्ष के कार्यक्रम प्रदेश में 2 अक्टूबर, 2020 तक आयोजित किए जाने का उद्देश्य यही है कि गांधी जी के विचार जन-जन तक पहुंचे और युवा इनसे प्रेरणा ले सकें। (शेष पृष्ठ 3 पर)

डॉ. अम्बेडकर विचार मंच ने मनाया गणतंत्र दिवस

जयपुर। डॉ. अम्बेडकर विचार मंच (समिति) की ओर से 71वां गणतंत्र दिवस कल्याणजी का रास्ता, बाल निवास के सामने, जयपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया।



मानवाधिकार जयपुर शहर अध्यक्ष इत्यादि ने शिरकत की। इस अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशिक्षण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

समिति के महासचिव राजेन्द्र कुमार बैरवा ने बताया कि इस अवसर पर अतिथि के रूप में श्री रजनीश गुप्ता वरिष्ठ भाजपा नेता, महेश धावनिया प्रदेशाध्यक्ष प्रान्तीय बैरवा प्रगति संस्था, मेहता राम काला जयपुर शहर अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर विचार मंच, हरिनारायण बैरवा समाजसेवी, मोहन पारीक प्रदेशाध्यक्ष मजदूर संघ, गोपाल सिंह चौहान सचिव जिला शहर कांग्रेस कमेटी, बी. लाल अहमद राष्ट्रीय

भारत पर्व में लाल किले पर 'कालबेलिया नृत्यांगनाओं' ने समा बाँधा, राजस्थान के लोक कलाकारों ने मचाई धूम

जयपुर। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में आयोजित छह दिवसीय भारत पर्व -2020 में राजस्थान के लोक कलाकारों ने अपनी नायाब प्रस्तुति 'कालबेलिया नृत्य से समा बाँधा' दिया और अपने दिलकश गीतों व संगीत की सुमधुर प्रस्तुतियों से लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया।

सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा चरी, तेरहताल, गैर, चकरी और कालबेलिया लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां हुईं। लगभग डेढ़ घंटा चले इस मनमोहक कार्यक्रम के प्रारंभ में निवाई से आए रामप्रसाद शर्मा और साथी कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। उसके उपरांत अनीशुदीन के अगुवाई में स्थानीय नृत्यांगनाओं द्वारा चरी नृत्य की प्रभावी प्रस्तुति की गई।

11 हजार से ज्यादा रोटेरियंस ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड



मैराथन को रवाना करते राज्यपाल कलराज मिश्र, आरसीए प्रेसिडेंट वैभव गहलोत, मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर सहित अन्य अतिथि।

जयपुर। अल्बर्ट हॉल पर हजारों रनर्स का जोश, जुनून और जज्बा दिखा। हर उम्र के पार्टिसिपेंट्स में गर्मजोशी दिखाई दी। कोहरे के कारण 100 मीटर से ज्यादा तक की विजिबिलिटी होने के बावजूद रनर्स सही समय पर मौजूद थे। सुबह 3:30 बजे प्रोफेशनल्स ने फुल मैराथन (42 किमी) शुरू की।

एयू बैंक जयपुर मैराथन 2020 पावर्ड बाय दैनिक भास्कर में रविवार की सुबह

हजारों लोगों ने 'क्लीन जयपुर और फिट जयपुर' का संदेश दिया। वहीं रोटरि क्लब के 11,339 रोटेरियंस ने मैराथन में एक साथ हिस्सा लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावेदारी पेश की है। इसकी पुष्टि गिनीज बुक के प्रतिनिधि ऋषि नाथ ने की है। इस मौके पर गवर्नर कलराज मिश्र, कैबिनेट मंत्री बी.डी. कल्ला, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, बॉलीवुड डायरेक्टर मधुर भंडारकर (शेष पृष्ठ 2 पर)

बैरवा समाज का चतुर्थ युवक-युवती परिचय सम्मेलन 23 फरवरी को जयपुर में

जयपुर। प्रान्तीय बैरवा प्रगति संस्था की ओर से बैरवा समाज का चतुर्थ युवक-युवती परिचय सम्मेलन 23 फरवरी, 2020 को प्रातः 10 बजे पिक सिटी प्रेस क्लब, नारायणसिंह सर्किल, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

संस्था के अध्यक्ष महेश धावनिया ने बताया कि इस अवसर पर बैरवा समाज के कलाकारों द्वारा राजस्थानी एवं फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियां एवं सांस्कृतिक

कार्यक्रम भी किया जायेगा। इस कार्यक्रम के साथ ही प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, समाज के भामाशाओं एवं दानदाताओं का सम्मान भी किया जायेगा। परिचय सम्मेलन में भाग लेने हेतु इच्छुक युवक-युवती अपना पंजीयन संस्था कार्यालय सी-57, महेश नगर, जयपुर में करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मो. 9928260244, 7073909291, 9414441044 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन 25 फरवरी को

जयपुर। न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से 1सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन 25, फरवरी, 2020 (फुलेरा दोज) को शीतला माता चाकसू में होने जा रहा है। ऐसे परिवार जो अपनी बेटी की शादी का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं वह अपनी



दिए गए हैं नंबर पर सम्पर्क करे शादी पुरा खर्च न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से किए जायेगा व हर लाडली बेटी का नया जीवन शुरू करने के लिए संस्थान की ओर से विशेष उपहार में 100 वर्ग गज भूमि व 1 लाख रुपए मूल्य करीब का घर उपयोगी सामान उपहार मर्जी से बेटी का रिश्ता करने के बाद निचे स्वरूप दिया जायेगा। मो. 8187877778

180 सदस्यों ने दिया सामाजिक जागरूकता का संदेश

जयपुर। समर्पण संस्था के 180 सदस्यों ने एयू जयपुर मैराथन में पर्यावरण, स्वच्छता व सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। संस्था सदस्यों ने टीम के साथ 6 किमी ड्रीम रन में भाग लिया। इस ड्रीम रन में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉ. दौलत राम माल्या के निर्देशन में सदस्यों के हाथों में 25 सामाजिक जागरूकता संदेशों की तख्तियां थीं। दौड़ में संस्था के मुख्य संरक्षक धर्मपाल, द्वारका प्रसाद बुनकर,

रामजी लाल बैरवा, उपाध्यक्ष रामदयाल बैरवा, संयुक्त सचिव सिमरन चौधरी व



राकेश संचेती, संरक्षक सुमित्रा पाल सहित 180 सदस्य शामिल रहे।

समाचार विज्ञापन संकलन

श्री बाबा समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि प्रत्येक माह की 5 तारीख है। अतः समाचार एवं विज्ञापन आदि के प्रकाशन के लिए विज्ञप्ति, फोटो आदि सामग्री माह की 20 तारीख तक पूर्ण विवरण के साथ भिजवा दें। सम्पर्क करें:

श्री बाबा whatsapp 7073909291

सी-57, महेश नगर, 80 फीट रोड, जयपुर-15

मो.-9928260244 E-mail : shreebaba_2008@yahoo.com

सम्पादकीय पीएफआई का धन

प्रवर्तन निदेशालय या ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खातों की जांच से जो जानकारीयां सामने आई हैं, उनसे नागरिकता संशोधन विरोधी कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में उसकी भूमिका का आरोप पहले से ज्यादा पुख्ता होता है। ईडी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में माना है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के बैंक खातों में लेन-देन का विस्तृत ब्योरा उसकी भूमिका को संदिग्ध बना देता है। यह खबर पहले ही हमारे सामने आ चुकी है कि ईडी ने पीएफआई के खिलाफ मनी लॉड्रिंग की जांच शुरू की थी। इस दौरान उसके सहयोगी संगठनों के 73 बैंक खातों में 120 करोड़ रुपये जमा कराने के प्रमाण हैं, और एक-दो दिन के भीतर उसमें से अधिकांश रकम निकाल भी ली गई। पीएफआई कुछ भी कहे लेकिन इसका जवाब तो उसे देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ ? हिंसक प्रदर्शनों के दौरान बैंक खातों से तो एक दिन में कई-कई बार पैसे निकाले गए। बारह दिसम्बर को एक खाते से 90 बार निकासी की गई थी। पीएफआई के नेहरू प्लेस (दिल्ली) स्थित खाते के साथ ही उत्तर प्रदेश में बहराइच, बिजनौर, हापुड़, शामली, डासना जैसी जगहों के खातों में भारी मात्रा में बार-बार नकदी जमा की गई। हिंसक प्रदर्शन के दिन या उससे एक दिन पहले इतनी निकासी शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए तो नहीं हो सकती। ऐसे में ईडी का यह निष्कर्ष सच लगता है कि छह जनवरी तक सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के लिए पीएफआई ने धन की व्यवस्था की थी। छह जनवरी के बाद की जांच जारी है।

वस्तुतः नागरिकता कानून विरोधी हिंसा की साजिश और उसे अमल में लाने में पीएफआई की भूमिका के बारे में कई राज्यों की पुलिस ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी हुई है। किंतु ऐसे खतरनाक संगठन को प्रतिबंधित करने से पहले ठोस आधार जरूरी है जिससे कि वह न्यायालय में टिक सके। इसलिए केंद्र हर पहलू की जांच करवा रहा है। पीएफआई के खातों की जांच इसी प्रक्रिया का अंग है। पीएफआई पर लंबे समय से सांप्रदायिक हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, और अलग-अलग मामलों में इसके सदस्यों को सजा भी हुई है, लेकिन इस तरह देशव्यापी योजना बनाकर वह हिंसा करा देगा शायद इसकी कल्पना खुफिया एजेंसियों को नहीं थी। बहरहाल, नई जानकारी के बाद आवश्यक हो गया है कि केंद्र सख्ती दिखाए एवं इसे प्रतिबंधित कर इसके सदस्यों को जेल की सलाखों में डाले।

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता

100 रुपए

विशिष्ट द्विवार्षिक सदस्यता

500 रुपए

साथ में पाएं दो वैवाहिक एवं एक

क्लासीफाइड डिप्लोमा

विज्ञापन

बिल्कुल मुफ्त

आजीवन सदस्यता

2100 रुपए

संरक्षक सदस्यता

5100 रुपए

सामाजिक क्रान्ति के उन्नायक: डॉ. भीमराव

भारत का सामाजिक जीवन अत्यन्त विविधतापूर्ण और उसकी सामाजिक संस्थाएं सतत् प्रवाहमान हैं। दृष्टव्य है कि जटिल सामाजिक परम्पराओं के साथ सांस्कृतिक बंधन भी निरन्तरता से गतिमान हैं। प्राचीन काल से ही चातुर्वर्ण्य प्रणाली पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में जहाँ छूआछूत दृष्टिगोचर है, वहीं संवैधानिक रक्षोपाय के सन्दर्भ में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। यही कारण है कि जहाँ पूर्व में उन्हें 'दलितों के मसीहा' के रूप में इंगित किया जाता था वहीं आज उन्हें 'राष्ट्र निर्माता', 'विधि वेत्ता' व 'सामाजिक न्याय के प्रवर्तक' के रूप में जाना जाता है। डॉ. अम्बेडकर ने भारत में संघर्ष को न केवल गति प्रदान की वरन् सामाजिक सरोकारों व सामाजिक न्याय के उद्धारक के रूप में नया आयाम और परिवर्तन की नई दिशा प्रदान की।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सन् 1929 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जिससे कि अस्पृश्यता का दंश झेल रहे वर्ग को शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की सहायता करने और सरकार के समक्ष उनकी शिकायतें प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया। इस संगठन का सिद्धान्त वाक्य था 'पिहित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' इस संगठन ने अस्पृश्य समझे जाने वाले दलित समाज के लिए छात्रावास, पुस्तकालय और

अध्ययन कक्ष खोले व इन्हें आत्म-सम्मान

की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने



अछूतों को स्वाभिमान से जीने व मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा- 'यह सही समय है कि हमने

हमारे मन से विकास सर्वाधिक इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति है तथा उस समाज में महिलाओं का क्या स्थान है? यही बात भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों पर भी समरूप लागू होती है। डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज में दलितों की स्थिति से स्वयं परिचित थे, उन्हें स्वयं को दलित होने के कारण पग-पग पर उपेक्षा और उपहास का दंश झेलना पड़ता था। इन सब मुद्दों व बातों को उन्होंने प्रेरणा के रूप में लिया व स्वस्फुरित

अभिप्रेरण के रूप में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए उन्होंने एक क्रान्तिकारी पुरोधा के रूप में आवाज उठाई व सक्रियता से कार्य किया। समाज के निम्न स्तर के लोगों के साथ शोषण के ऐसे कई मामले हैं, जिन्होंने बदलाव के लिए ऊर्जा का संचार किया। वे सत्य, न्याय और पक्षपात-विरोधी आन्दोलन से प्रेरित थे। वे समाज के भेदभाव के खिलाफ थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि पिछड़ों और दलित वर्गों को राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। जिससे कि वे सामाजिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। अम्बेडकर ने अछूतों को उनके आत्म उत्थान के लिए संघर्ष की दिशा में प्रेरित किया। अछूतों और दलित वर्ग के सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा के लिए वे भारत में दलितों के आन्दोलन के मार्टिन लूथर किंग थे। वे स्वयं भी विदेशी शिक्षा के बावजूद, अपने निम्न जाति के कारण अपमान झेल चुके थे। वे कर्कर दलित भेदभाव के शिकार थे।

क्रमशः

वैवाहिक

वर चाहिए

- * जयपुर निवासी, 23 वर्ष, शिक्षा-बी.कॉम, पिता-निजी कार्य, गौत्र-गंगवाल, गोगडिया, लोदवाल, सिंवतिया व सामने चरावण्डिया न हो, मो. 9549367702
- * जयपुर निवासी, 21 वर्ष, शिक्षा-बी.कॉम, पिता-निजी कार्य, गौत्र-गंगवाल, गोगडिया, लोदवाल, सिंवतिया व सामने चरावण्डिया न हो, मो. 9549367702
- * जयपुर निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-एम.ए., बी.एड, पिता-निजी कार्य, गौत्र-गोठवाल, घुणावत, कुण्डारा, सामने माली न हो, मो. 7232830378
- * जयपुर निवासी, 26 वर्ष, शिक्षा-बी.कॉम, पिता-निजी कार्य, गौत्र-गोठवाल, बंशीवाल, मीमरोट, सामने सुलानिया न हो, मो. 9351759022
- * जयपुर निवासी, 30 वर्ष, शिक्षा-एम.ए., बी.एड, एम.एस.सी., पिता-निजी कार्य, गौत्र-बंशीवाल, गोठवाल, सुलानिया।
- * जयपुर निवासी, 25 वर्ष, शिक्षा-एम.ए., पी.जी.डी.सी., पिता-निजी कार्य, गौत्र-गोठवाल, घुणावत, कुण्डारा, सामने माली न हो।
- * जयपुर निवासी, 25 वर्ष, शिक्षा-एम.ए., पिता-निजी कार्य, गौत्र-बड़गोती (लालावत), बंशीवाल, सांवलिया।
- * जयपुर निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-बी.कॉम, पिता-निजी कार्य, गौत्र-बेथेड़ा, नागरवाल, लोदवाल, सामने भियाणा न हो, मो. 8560026938
- * जयपुर निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-बी.ए., आईटीआई, पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-नगवाडा, कुण्डारा, जोनवाल, सामने मेहर न हो, मो. 8302594945
- * जयपुर निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-बी.कॉम, पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-नगवाडा, कुण्डारा, जोनवाल, सामने मेहर न हो, मो. 8302594945
- * टोंक निवासी, 29 वर्ष, शिक्षा-एम.ए., वर्तमान में प्राइवेट नौकरी दिल्ली में, पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-नागरवाल, लोदवाल, मरमत।
- * दौसा निवासी, 29 वर्ष, शिक्षा-बी.ए., एम.बी.ए., फैशन डिजाइनर, पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-मीमरोट, माली, गोठवाल।
- * जयपुर निवासी, 30 वर्ष (विधवा), शिक्षा-एम.ए., पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-नागरवाल, गुमलाड़ा, मेहरा।

वधु चाहिए

- * फुलेरा-जयपुर, 50 वर्ष, (विधुर) शिक्षा-एम.ए., वर्तमान में एल.आई.सी. एजेंट, मासिक आय-16,000 रुपये, गौत्र-गोठवाल, देवतवाल, बेथेड़ा।
- * टोंक निवासी, 34 वर्ष, शिक्षा-एम.एस.डब्ल्यू, वर्तमान में संविधाकर्मी लेबर डिपार्टमेंट, मासिक आय-25000 रुपये, पिता निजी कार्य, गौत्र-लोदवाल, बड़ोदिया, रेणियाल, परालिया।
- * जयपुर निवासी, 31 वर्ष, शिक्षा-एम.ए., बी.एड., टेट, रीट, पिता राजकीय सेवा, गौत्र-लोदवाल, जाटवा, गंगवाल।
- * टोंक निवासी, 32 वर्ष, शिक्षा-12वीं पास, वर्तमान में राजकीय सेवा (फॉर्थ क्लास), गौत्र-चरावण्डिया, गजरानिया, मेहरा, नागरवाल।
- * टोंक निवासी, 35 वर्ष (तलाकशुदा), शिक्षा-बी.ए., वर्तमान में प्राइवेट जॉब, मासिक आय-12 हजार रुपये, पिता निजी कार्य, गौत्र-जाटवा, उज्ज्वल, गोठवाल।
- * फरीदाबाद निवासी, 30 वर्ष, शिक्षा-बी.टेक. इलेक्ट्रीकल, वर्तमान में बिल्डर का कार्य, पिता निजी कार्य, गौत्र-मरमत, जाटवा, मुराडी।
- * जयपुर निवासी, 36 वर्ष, (तलाक सुदा) शिक्षा-बी.एड., वर्तमान में टेलरिंग का कार्य, पिता निजी कार्य, गौत्र-गोठवाल, नागरवाल, मीमरोट, कुण्डारा।
- * टोंक निवासी, 26 वर्ष, शिक्षा-एम.बी. आई.टी., वर्तमान में प्राइवेट कार्य, गौत्र-कुवाल मरमत, बीलवाल।
- * लाखेरी निवासी, 27 वर्ष, शिक्षा-बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, वर्तमान में आई.टी. कम्पनी में कार्यरत, पिता राजकीय सेवा, गौत्र-जाटवा, सीवतिया, टटवारिया, मो. 8580692811
- * जयपुर निवासी, 34 वर्ष, (तलाक सुदा) शिक्षा-बी.ए., एम.ए., वर्तमान में सिस्टम इंजिनियर, गौत्र-भीमवाल, रेशवाल, मीमरोट, मो. 9950917562
- * जयपुर निवासी, 31 वर्ष, शिक्षा-बी.ए., एम.ए., एम.बी.ए., एस.एस.सी. पास, पिता राजकीय सेवा, गौत्र-बंशीवाल, नागरवाल, सुलाणिया, सामने बेथेड़ा ना हो।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें, मो.: 9928260244

11 हजार से ज्यादा रोटेरियंस ने बनाया... (पृष्ठ 1 का शेष)

संस्कृत युवा संस्था के संरक्षक लोकेन्द्र सिंह कालवी और एयू बैंक एमडी संजय अग्रवाल ने फ्लैग ऑफ किया। सुबह 5:30 बजे हाफ मैराथन (21 किमी) शुरू हुई। मैराथन के सीईओ मुकेश मिश्रा ने बताया कि इस दौरान एक हजार से अधिक राजस्थानी लोक कलाकारों और तीन आर्मी बैंडों ने प्रस्तुतियां दीं। संस्कृतिक युवा संस्था के प्रेसिडेंट सुरेश मिश्रा और वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चेयरमैन अनूप बरतरिया ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

वर्ल्ड रिकॉर्ड का गवाह बनी जयपुर मैराथन: एशिया की सबसे बड़ी मैराथन रेसों में से एक जयपुर मैराथन ने इस बार

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। रेस में देशभर से जुटे 11,339 रोटेरियंस ने एक जैसी टीशर्ट पहनकर अल्बर्ट हॉल से वर्ल्ड ट्रेड पार्क तक 6 किमी की ड्रीम मैराथन में दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

क्लब अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया, 14 देशों के युवा रोटेरियंस ने इस मैराथन में भाग लिया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि ऋषि नाथ ने मैराथन में मौजूद रहकर 11,339 लोगों के कीर्तिमान में भाग लेने की पुष्टि की। वहीं रेट्रो रनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एयू बैंक जयपुर मैराथन में ब्रेक हुआ।



जयपुर दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रम प्रमुख डॉ. ओमप्रकाश जी को गोपीलाल गोठवाल स्मृति संस्थान के अध्यक्ष ताराचन्द गोठवाल की ओर से नववर्ष 2020 की डायरी व अन्य सामग्री देकर बधाई देते हुए।

इंजीनियरिंग कॉलेजों के सरकारी होने से सबको लाभ ही है

लगभग महीने भर से चल रही राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की मुहिम कुछ रंग लाई है। कल दिनांक 19 दिसम्बर 2019 को विभाग के माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि उनकी पहली प्राथमिकता इन सभी कॉलेजों को पूर्णतः सरकारी घोषित करवाने की रहेगी। दूसरी प्राथमिकता इन सभी कॉलेजों को राजस्थान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी या बीकानेर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी का संघटक कॉलेज बनाने की रहेगी। मंत्री जी की उक्त घोषणा स्वागत योग्य है। आखिरकार इन कॉलेजों में पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों का दोष क्या है जो इनको पूर्णतः सरकारी का दर्जा नहीं दिया गया है ? निर्विवाद रूप से विज्ञान के साथ गणित या जीव-विज्ञान आज भी सर्वोच्च रूप माना जाता है। यदि दसवीं में छात्र के अच्छे अंक नहीं आते तो उसे ये रूप नहीं दिये जाते हैं, कॉमर्स या आर्ट्स दे दिया जाता है। फिर वह कितनी ही मेहनत करे, कभी उसे ये रूप मिल ही नहीं सकते हैं। अतः यह सर्व विदित है कि मात्र मेहनती छात्रों को ही विज्ञान-गणित या विज्ञान-बायोलॉजी मिलता है। बारहवीं के साथ ही या बाद में विद्यार्थी कठोर संघर्ष करके मेडिकल या इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिये चयनित हो पाता है। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का एक सपना होता है, जो कि चार साल की कठोर मेहनत के बाद उसे हासिल होती है। नौकरी के कई रास्ते उसके सामने खुल जाते हैं।

इन्हीं रास्तों में से एक है-इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्यापन कार्य कराना। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षण कार्य हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता मास्टर डिग्री (एम ई/एम टेक) है। इतने प्रयासों के बाद जब कोई व्यक्ति सहायक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनता है तो परिवार और समाज में उसका मान-सम्मान बढ़ता है और वह भी अपने-आपको समाज और देश का जिम्मेदार सदस्य समझकर गौरवान्वित महसूस करता है।

लेकिन कुछ समय बाद उसे लगने लगता है कि अध्यापन कार्य में आकर उसने गलती कर दी है, खास तौर पर राजस्थान में। इसे इस तरह समझ सकते हैं- एक स्नातक व्यक्ति सरकारी विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त होता है। 5-8 साल बाद वह सहायक अभियंता बन जाता है, 5 साल बाद कार्यकारी अभियंता, 5 या सात साल बाद अधीक्षण अभियंता और 5 साल बाद मुख्य अभियंता बन जाता है। वैसे कई और भी कारक हो सकते हैं जिनके चलते यह समय सीमा कमीबेशी हो सकती है, पर आम तौर पर प्रमोशन इसी प्रकार होते रहते हैं।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्या हाल है, वह देखिये। उक्त व्यक्ति का साथी उसी के साथ राजस्थान के किसी स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुआ। वह छह साल बाद भी उसी ग्रेड-पे में चल रहा है, 12 साल बाद भी और 18 साल बाद भी!! जबकि वह एम टेक भी कर चुका है और इंजीनियरिंग में पीएच डी कर रहा है या कर चुका है। उसका साथी मुख्य अभियंता बन गया है और यह अभी भी सहायक प्रोफेसर में ही कलम घिसाई कर रहा है। यहाँ तक कि अकेडमिक कॉलेजों में जो उसके साथी हैं जिनके दसवीं में उससे कम नम्बर आने के कारण विज्ञान-गणित नहीं मिला था या जिनको बाद में इंजीनियरिंग में अवसर नहीं मिला और जो एमएससी करके सहायक प्रोफेसर बने, वे भी अच्छे पद और वेतन श्रृंखला में हैं।

किसी भी देश अथवा भू-भाग के विकास में विज्ञान का बहुत योगदान होता है। विज्ञान के ही कई आयाम हैं जिनमें तकनीकी, इंजीनियरिंग मेडिकल आदि से

लगभग सभी परिचित हैं। आज यदि अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस, जापान, फ्रांस आदि देश हमसे आगे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकतर अविष्कार इन देशों में हुए हैं और दूसरे देशों ने उनके पेटेंट खरीदे हैं या उनका उपयोग-भर किया है। इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये कॉलेजों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कम कीमत पर यह शिक्षा विद्यार्थियों तक पहुँचना भी चाहिये और कॉलेजों में रिसर्च के प्रति अभिरुचि और सुविधायें भी होना चाहिये। हमारे देश के कोने-कोने में ऐसी प्रतिभाएं बिखरी हुई हैं जिन्हें मात्र आर्थिक सम्बल भी समय पर मिल जाये तो देश का नाम दुनिया में रोशन कर सकती हैं।

सरकारी स्तर पर यही कार्य सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल कर किया जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज स्वायत्तशासी हैं। इनकी अपनी-अपनी सोसायटी हैं, अपना-अपना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेते हैं, जो कि सिर्फ उसी कॉलेज पर लागू होते हैं। होने को तो 100 के आसपास प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, पर एक तो इनकी शिक्षा महंगी है, अलग से कई प्रकार के चार्ज इनके द्वारा वसूले जाते हैं और इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना मात्र होता है, रिसर्च, सबको सस्ती शिक्षा और जनहित इनके प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल नहीं होते हैं। अतः ये सर्व सुलभ नहीं कहे जा सकते हैं। आज के युग को देखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य के सभी स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूर्णतः सरकारी कॉलेजों का दर्जा दे दिया जाये और इनका सारा हिसाब-किताब भी राज्य सरकार के ही अधीन हो। इससे आम जनता से लेकर कार्मिकों और सरकार तक, सबको फायदा ही फायदा होगा।

1. छात्रों को रोजगार मिलने में आसानी:-वैसे डिग्री यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन सब कोई जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों और सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई और सुविधाओं के स्तर में कितना अंतर होता है। यह बात नियोजक भी जानते हैं और इसी के आधार पर छात्रों का प्लेसमेंट होता है।

2. जनता को लाभ:-वर्तमान में स्ववित्तपोषित सीट पर लगभग 70-75 हजार रुपये प्रतिवर्ष फीस ली जाती है। अगर कॉलेज सरकारी हो जाते हैं तो ट्यूशन फीस माफ हो जायेगी, अतः ली जाने वाली फीस लगभग आधी हो जायेगी। इससे निर्धन छात्रों की आर्थिक परेशानी कम होगी।

इसके अलावा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलने लगेगी।

अमीरी-गरीबी का भेद मिटाती... (पृष्ठ 1 का शेष)

उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री का गांधी जी एवं खादी के प्रति विशेष लगाव है। प्रदेश में पहला अवसर है जब खादी वस्त्रों पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि नए बुनकर और नए कालिन तैयार हों ताकि नई पीढ़ी खादी के महत्व को समझे। मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता ने कहा कि खादी का रिश्ता हमारे इतिहास और परम्पराओं से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी और आजादी को एक-दूसरे का पूरक बना दिया था। खादी को आगे बढ़ाने के लिए इसे आधुनिक फैशन के अनुरूप बदलना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री सुबोध अग्रवाल ने कहा कि खादी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने रिवाँल्विंग फंड 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। बीकानेर में

में पिछले तीन वर्षों से टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा में छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्य देख रहा हूँ। सरकार के नियमानुसार आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति तभी मिलती है, जब वे राजकीय कॉलेजों में ही पढ़ रहे हों। जब भी हमारे कॉलेज का कोई छात्र इस कैटेगरी में फर्म भरता है, उसका फर्म उपरोक्त कारण से रद्द हो जाता है। पिछले कई सालों से इस कॉलेज से इस वर्ग के किसी भी छात्र को इसी कारण कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अपने स्तर पर हम सभी कोशिशें कर चुके हैं, पर कॉलेज को सरकारी बनाना तो राज्य सरकार का ही कार्य है। इससे निर्धन वर्ग के छात्रों को दोहरा लाभ होगा, एक तो फीस ही कम लगेगी, दूसरे उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल सकेगी।

3. कॉलेज के प्राचार्य और वरिष्ठों के एकाधिकार का खाम्मा:-अभी स्वायत्तशासी होने से ये अपने नीतिगत फैसले स्वयं ले सकते हैं। कई बार इनके निर्णय छात्रों और कर्मचारियों के विरोध में होते हैं तो कई बार ऐसे निर्णय लेते ही नहीं हैं जो कि कर्मचारियों के हित के हों। उदाहरणार्थ-चाहे जिस व्यक्ति को कॉलोनी में क्वार्टर अलॉट कर देना और जिसको आवश्यकता हो, उसे नहीं देना, यहाँ तक कि जिसका स्वयं का मकान कॉलेज की बगल में हो, उससे वर्षों तक क्वार्टर खाली नहीं करवाना, छात्रों के लिये कैण्टीन आदि की सुविधा न होने देना, पुस्तकालयों की व्यवस्था सही नहीं होने देना, ताकि सम्बन्धियों की दुकानें ठीक से चल सके। कॉलेज में सार्वजनिक सुविधाओं की साफ-सफाई में जानबूझकर लापरवाही करने देना और जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सुनवाई नहीं करना, क्योंकि प्राचार्य का वरदहस्त होना, बेकार सामानों को जब तक पूर्णतः कबाड़ में नहीं बदल जाये, नहीं बेचना, आदि। और भी कई कार्य ऐसे होते हैं जिनसे पदस्थ उच्च कर्मचारियों के एकाधिकार की झलक मिलती है। इससे गरीब तबके के तथा आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारी मन-मारकर नौकरी करने को विवश होते हैं, जबकि उच्च पदस्थ और आर्थिक रूप से सम्पन्न कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे कॉलेज में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का मामला इसी कारण से आज तक अटका पड़ा है। वैसे इस स्कीम से हर फेकल्टी मेंबर की ग्रेड पे बढ़नी थी। किसी की 6000 से 7000 तो किसी की 7000 से 8000, कुछ की 8000 से 9000 व 9000 से 10000 भी होनी थी और इस प्रकार लगभग सभी को फायदा होना था, परन्तु पचासों बार मीटिंग की, कभी 2-3 तो कभी 5-7 मेंबरों से अधिक नहीं आये। गम्भीरता से किसी ने इस मामले को लिया

ही नहीं और फिर प्राचार्य तथा लेखाधिकारी इसी पूट का फायदा उठा कर मनमाने ढंग से नचाते रहे। आज राज्य के कई इंजीनियरिंग कॉलेजों को न केवल 6000 से 7000 ग्रेड पे का फायदा मिल चुका है, बल्कि 7000 से 8000 का फायदा भी मिल चुका है और आगे की ग्रेड पे के लिये उनकी फाइलों पर कार्रवाही चल रही है और आचार संहिता लगने से पहले-पहले सारे लाभ उन्हें मिल सकते हैं। हमारे कॉलेज में 6000 से 7000 के लिये तरस रहे हैं!!

पूर्णतः सरकारी कॉलेज होने से यह फायदा होगा कि स्पष्ट गाईड लाईन होगी कि यह कार्य करना होगा और यह नहीं। साथ ही इस कैडर के कर्मचारी को यह लाभ-परिलाभ कब-कब मिलने हैं, सब स्पष्ट होगा। अगर ये कॉलेज सरकारी होते तो फेकल्टी मेंबरों को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। नियमानुसार जितने भी लाभ-परिलाभ मिलने होते, वे समय पर मिल जाते और किसी तरह की कडुवाहट नहीं रहती। कई योजनाएं केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये ही होती हैं जिनका फायदा आज तक स्वायत्तशासी संस्थानों के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, वह भी सरकारी होने पर मिलने लग जायेगा।

4. समय का सदुपयोग अध्यापन, रिसर्च और कॉलेज के विकास कार्यों में कर सकेंगे:- जैसा कि पूर्व के बिन्दू में लिख चुका हूँ- हमारे कई फेकल्टी मेंबरों को पाँचवें वेतनमान का तो कईयों को छठे

वेतनमान के अनुरूप मिलने वाले लाभ का इंतजार हैं। इसी को लेकर कर्मचारी लगभग 6-7 साल से संघर्षरत हैं। हमारे हजारों घण्टे और हजारों रुपये इस बेकार के बेहूदा काम में फुँक चुके हैं। अगर यह कॉलेज सरकारी होता तो, जो समय बेकार में कार्यों में व्यर्थ हुआ, वह छात्रों के उचित अध्यापन में, रिसर्च या कॉलेज के विकास हेतु कार्य करने में व्यतीत होता। अब भी यदि कॉलेज सरकारी हो जाता है तो आगे समय का सदुपयोग हो पायेगा।

5. वैज्ञानिक तरक्की को बढ़ावा मिलेगा:-यह एक दुखद पहलू है कि इंजीनियरिंग, तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र के फेकल्टी मेंबरों को अपने हक पाने के लिये धरने और प्रदर्शनों पर बैठना पड़ता है। जिनका समय प्रयोगशालाओं में छात्रों के साथ किसी तकनीकी समस्या पर वाद-विवाद करने और उसे सुलझाने में व्यतीत होना चाहिये, वह समय धरने और प्रदर्शनों जैसे फिजूल के कार्यों में जाया हो रहा है।

पूर्णतः सरकारी कॉलेज कॉलेज होने से जो भी निर्णय होगा, वह सभी कॉलेजों पर समान रूप से लागू होगा और उसका कोई विरोध भी होगा तो समाधान भी शीघ्र ही हो जायेगा।

अतः जितना जल्दी हो सके, सरकार को राज्य क सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूर्णतः सरकारी कर देना चाहिये।

श्याम सुन्दर बैरवा
सहायक प्रोफेसर (वस्त्र रसायन)

हर्ष के दोहे

गतांक से आगे

जहाँ सुमति वहाँ सम्पदा, हर्ष रहे मिल एक।

संगठन में गुण सौ भले, संकट टलें अनेक।।

जहाँ सुमति होती है, और, संगठन में कई गुण होते हैं। संगठित रहते हैं। और, संगठन में कई गुण होते हैं। संगठित रहने से अनेक संकट अपने आप टल जाते हैं।

दुर्योधन पाले रहे, या रावण के संग।

हर्ष रहे सब घाटी में, जो भी पड़ा कुसंग।।

चाहे कोई दुर्योधन के पक्ष में रहा हो या रावण के संग, हर कोई हमेशा घाटे में ही रहा। यह सच है कि कुसंग में पड़ा व्यक्ति हमेशा घाटे में ही रहेगा।

हर्ष धरा को रौंधता, अकड़ भरा मन मोद।

दो दिन रहता सहज से, आखिर माटी गोद।।

जिस व्यक्ति में अकड़ है, धरा को रौंधते हुए चलता है, जिसका मन घमण्ड से भरा हुआ है, वह यही नहीं जानता कि यहाँ दो दिन रहना है, सो सहज से रहे। आखिर सभी को मिट्टी के गोद में सो जाना है।

हर्ष जौहरी जानता, तोल मोल व्यवहार।

बिन पासंग की ताखड़ी, तुलता खरपतवार।।

सच्चा जौहरी जानता है कि हीरों का तोल-मोल कैसे करते हैं और उनका बेचना किस तरह किया जाता है। बिना पासंग की तराजू से तो केवल खरपतवार ही तुलता है।

संदल शीतल सुगंध भी, हर्ष जले तो दाह।

सीमा तक शीतल रहे, हाथी सज्जन शाह।।

चंदन शीतल और सुगंधित होता है, परन्तु जलने पर तस से जलाता भी है। चंदन की तरह हाथी, सज्जन लोग और शाह एक सीमा तक ही शांत रहते हैं।

पर पीड़ा ना जानते, हर्षा जो बेपीर।

पीर पराई वो हरे, रहते दुःख में सीर।।

जो व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को नहीं जानते, वे बेपीर हैं। जो व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को हरने या मिटाने में लगे रहते हैं, उनका दूसरों की पीड़ा में साझा होता है।

रावण मांगी दो घड़ी, अंत समय अरदास।

बाती बीते का कहे, थी पूरी ही पास।।

रावण जब मृत्यु शैय्या पर पड़ा था, तब उसने ईश्वर से दो घड़ी का समय और देने की प्रार्थना की। जीवन रूपी दीपक की बीती खत्म होने पर ऐसी प्रार्थना का क्या अर्थ? यदि वह कुछ करना चाहता था तो उसे समय रहते ही कर लेना था जबकि उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी थी।

— हरदान हर्ष
क्रमशः

मुख्यमंत्री गहलोत से मिला दलित अधिकार केन्द्र का प्रतिनिधि मण्डल

जयपुर। दिनांक 30 जनवरी 2020 को दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर का प्रतिनिधि मण्डल केन्द्र के मुख्य कार्यकारी

अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विति के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा पीडितों को दी जाने वाली सहायता

क्षमावर्द्धन के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाये।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संघोधन अधिनियम 2015 व नियम 2016 की पालना सुनिश्चित करने बाबत:- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में संघोधन कर और कई नये अपराधों को जोड़कर कई धाराएँ संघोधित एक्ट में जोड़ी गई है तथा पूरे देश व प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी 2016 से अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) संघोधन अधिनियम 2015 के नाम से इस अधिनियम को लागू किया गया व अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 2016 पूरे देश में 14 अप्रैल 2016 से लागू किया गया है।

लेकिन सरकार के प्रचार प्रसार के अभाव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण संशोधित कानून का लाभ दलितों को नहीं मिल पा रहा है। अतः इस अधिनियम की प्रभावी पालना के लिए अधिनियम के संघन प्रचार प्रसार के लिए व्यापक अभियान चलाया जावे तथा इस एक्ट के पालना करने वाले क्रमियों को प्रशिक्षण दिया जावे तथा प्रचार प्रसार के लिए अलग से बजट का प्रावधान रखा जावे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रतिनिधि मण्डल की सभी मांगों को ध्यान पूर्वक सुन कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।



पी.एल.मीमरौठ के नेतृत्व में केन्द्र के निदेशक सतीश कुमार, एडवोकेट, निदेशक, दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर व एडवोकेट चन्दा लाल बैरवा सहायक निदेशक, दलित अधिकार केन्द्र जयपुर ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मिलकर निम्न मांग की गई-

1. नियम 16 राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 संशोधन अधिनियम 2016 के नियम 16 के अनुसार राज्य सरकार राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग एण्ड विजिलेंस कमेटी के तहत तथा छः माह (जनवरी व जुलाई) में बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करने का प्रावधान है। जिसमें अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन, सहायता एवं पुनर्वास आदि योजना विभिन्न अधिनियमों तथा अधिकारियों की इसमें भूमिका पर चर्चा तथा पुनः नावलोकन किया जाये। प्रायः यह देखा गया है कि राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक पिछले 6 वर्षों से नियमित रूप से नहीं हो रही है जिसके कारण से उक्त अधिनियम का उपदेश्य ही समाप्त होता जा रहा है।

2. मोबाइल पुलिस स्टेशनों की स्थापना की जावे:- प्रायः यह देखा गया है कि दलित महिलाओं, दलित नाबालिग लड़कियों के साथ आये दिन सामूहिक बलात्कार, बलात्कार जैसी गम्भीर घटनाओं को अंजाम देने की घटनाओं का ग्राफ तेजगति से बढ़ता जा रहा है। घटनाओं को अंजाम देने के बाद में आरोपी घटना स्थल से फरार हो जाता है, पीडित महिलाएँ या पीडित परिवार को पुलिस थाने की दूरी होने के कारण से तुरन्त राहत व सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। जब पीडिता पुलिस थाने में न्याय व सुरक्षा की गुहार लगाती है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है तथा आरोपी को अपने बचाव करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। लाचार और साधन हीन पीडित का पुलिस की ओर से समय पर पर्याप्त सुरक्षा व न्याय इसलिए नहीं मिल पता कि पुलिस थाने सामान्यतः 15-20 किलोमीटर दूर होते हैं, पुलिस पहुंच नहीं पाती है और पीडित हार थक कर बैठ जाते हैं और न्याय से वंचित हो जाते हैं। अतः दलित अधिकार केन्द्र मांग करता है कि सरकार मोबाइल पुलिस स्टेशन खोले तथा इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बजट, संसाधन व अनुभवी व तकनीकी रूप से प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध करवाया जावे।

3. एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं विजिलेंस कमेटियों के सदस्यों को मनोनयन कर उन्हें सक्रिय व सशक्त बनाने बाबत:- नियम 17 के तहत गठित की गई जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं विजिलेंस कमेटियों की नियमित बैठकें नहीं हो पाती हैं और यदि होती हैं तो खाना पूर्ति की जाती है। अतः इन कमेटियों की नियमित बैठक व सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं विजिलेंस कमेटी

उत्पीडन के प्रत्येक केस में लगने के कारणों पर गहनता से जांच करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये जावे।

4. एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग एवं विजिलेंस कमेटियों का शीघ्र गठन कर उन्हें सक्रिय व सशक्त बनाने बाबत:- राज्य में दलित उत्पीडन की रोकथाम के लिए बने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व संघोधन अधिनियम 2016 के नियम 17-क, के तहत प्रत्येक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का प्रावधान है लेकिन अभी तक ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग व विजिलेंस कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। इसलिए सक्रिय व दलित मुद्दों पर समझ रखने वाले दलितों के प्रति सर्वेदनपील व कानूनों का ज्ञान रखने वाले लोगों को इन कमेटियों में शामिल किया जाये व ऐसे सदस्यों के



गोपी लाल गोठवाल स्मृति संस्थान के अध्यक्ष ताराचंद गोठवाल एवं सचिव श्रीमती सुशीला गोठवाल को श्री बाबा हिंदी मासिक समाचार पत्र की सदस्यता देते हुए प्रांतीय बैरवा प्रगति संस्था के प्रदेश अध्यक्ष महेश धावनिया।

शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि

लाल मोणा, परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास, सामाजिक न्याय एवं



(शहीद दिवस) के अवसर पर गुरुवार प्रातः शासन सचिवालय स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।

श्री गहलोत ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता गांधी जी एवं ज्ञात-अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रामधुनी एवं बापू के प्रिय भजनों का गायन किया गया। कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, उद्योग मंत्री श्री परसादी

अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी, श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री श्री भजन लाल जाटव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, खेल एवं युवा मामला राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना, मुख्य सचिव श्री डी. बी. गुप्ता सहित विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

400 लोगों की आंखों की जांच की और चश्मे बांटे

जयपुर। डॉ.अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी की ओर से निशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर

कैलगिरी आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में 400 लोगों की आंखों की जांच की गई और चश्मे बांटे गए। इसके



बाद मोतियाबिंद के 45 मरीजों को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। संस्था आयोजित किया गया। संस्था के महासचिव अनिल कुमार गोठवाल ने बताया कि

गोपीलाल गोठवाल स्मृति संस्थान द्वारा बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ के तहत चेक सौंपा

जयपुर। प्राइवेट सिविल सेवा के कार्यरत चेतन सिंह चौहान की

को संस्थान की सचिव सुशीला गोठवाल द्वारा श्रीमती मीता कुमावत प्रधानाध्यापिका

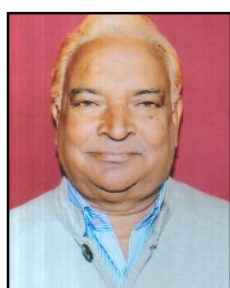
बेटी बीरा चौहान के लिए राजस्थान सरकार योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत गोपीलाल गोठवाल स्मृति संस्थान ने छात्रवृत्ति के द्वारा बेटी पढ़ाओ के सहयोग हेतु



जयपुर एकेडमी सैकण्डरी स्कूल गुलाब विहार, गांधी पश्चिम, लालपुरा, जयपुर

को 16 हजार रुपये का चेक भेंट किया ताकि बेटियों का भविष्य उज्ज्वल हो।

श्री बाबा समाचार पत्र के विशिष्ठ सदस्य बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं



ताराचंद गोठवाल
अध्यक्ष- गोपीलाल गोठवाल
स्मृति संस्थान, जयपुर



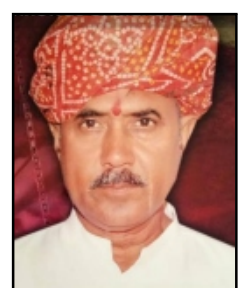
आनन्द प्रकाश राजलवाल
सेनि. सहायक अभियन्ता
विद्युत विभाग, जयपुर



रामअवतार बैरवा
सहायक लेखाधिकारी
कृषि विभाग, जयपुर



कन्हैयालाल भीमवाल
से.नि. कार्यालय सहायक
भू-जल विभाग, जयपुर



रामनिवास दास (मालपुरा)
महामंत्री
बैरवा गुरुकुल संत समिति



अशोक कुमार गोठवाल
सोडाला
जयपुर



संजय कुमार कूलवाल
ब्रांच पोस्ट मास्टर
भारतीय डाक वि., जयपुर



शिवचरण बैरवा
अध्यक्ष-बैरवा पंचायत समिति
बड़ा गुवाड़ा, जयपुर



देवीलाल बैरवा
बावड़ी
पालड़ी मीणा, जयपुर



श्योजीराम बैरवा
से.नि. सहायक कर्मचारी
कॉर्पोरेटिव बैंक, जयपुर